



न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, खेरवाडा  
जिला-उदयपुर(राज0)

निर्णय द्वारा पीठासीन अधिकारी  
प्रकरण संख्या- 07/2018 रा0 वा0

श्री जयसिंह- II (RAS)  
दायर दिनांक-09.03.2018  
निर्णय दिनांक-09.10.2025

1. श्रीमति हीरा बाई बेवा स्व.दलाजी प्रजापत, जाति-प्रजापत, निवासी-झुथरी, तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज0) ।
2. श्री गजेन्द्र पिता स्व. दला जी, जाति- प्रजापत, निवासी-झुथरी, तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज0) ।
3. श्री बसन्तिलाल पिता स्व. दला जी, जाति- प्रजापत, निवासी-झुथरी, तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज0) ।
4. श्री भगवतीलाल पिता स्व. दला जी, जाति- प्रजापत, निवासी-झुथरी, तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज0) ।
5. श्री कन्हैयालाल पिता स्व.दला जी, जाति- प्रजापत, निवासी-झुथरी, तहसील-खेरवाडा, जिला-उदयपुर(राज0) ।

■ -वादिगण-

बनाम

- 1 श्री नाथु पिता मावा जी जाति- पटेल, निवासी झुथरी, तहसील- खेरवाडा, जिला उदयपुर (राज0)।
- 2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खेरवाडा जिला उदयपुर (राज0)  
-प्रतिवादीगण-

वाद बाबत घोषणा, निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरस्ती कराने बाबत।

उपस्थित :- श्री विवेक कंसारा, अधिवक्ता वादीगण।

प्रतिवादी न.01 मय अधिवक्ता अनुपस्थित।

पैरोकार तहसीलदार खेरवाडा, उपस्थित।

-निर्णय-

दिनांक:- 09.10.2025

वादीगण के वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मौजा -झुथरी, तहसील -खेरवाडा, जिला- उदयपुर(राज0) की आराजी नम्बर 3532/0.04, 3533/0.04, 3534/0.03, 3535/0.46 कुल कित्ता 4 रकबा 0.57 हैक्टर कृषि भूमि वादीगण पुश्तैनी है उपरोक्त वर्णित आराजीयात के पुराने आराजी न0 2853 था जो की वादीयां संख्या 1 के पति व वादी संख्या 2 से 5 के पिता के नाम खाते दर्ज थी तथा उक्त वर्णित आराजीयात पर वादीगण का पुश्तैनी समय से कब्जा -काश्त होकर उपयोग-उपभोग कर रहे थे। वर्णित आराजीयात पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा था। परन्तु वादीयां न.1 के पति व वादी न. 2 से 5 के पिता की मृत्यु काफी समय पहले हो गई थी तथा उस समय वादी सं. 2 से 5 काफी छोटे थे, वादीगण का एक मात्र सहारा स्व. दलाजी थे जिसकी मृत्यु के पश्चात वादीयां न. 1 अपना व अपने बच्चो का पालन-पोषण करने रोजगार हेतु उदयपुर चली गई वही रोजगार कर अपने बच्चो का पालन पोषण करती रही एवं समय-समय पर आकर उक्त वर्णित आराजीयात की देख-भाल करती रहती थी। वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में वादीयां के बच्चे वादी संख्या 2 से 5 बड़े व समझदार होने क बाद वादी संख्या 2 ने उक्त वर्णित आराजीयात के खाते की नकल निकलवाने से जानकारी प्राप्त की तो पता चला की उक्त वर्णित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से खाते में दर्ज हो गई तब वादीगण ने सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त की तो पता चला की प्रतिवादी स. 1 ने पटवारी से मिली-भगत कर फर्जी बेचान के आधार पर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

भूमिधारी तहसीलदार -खैरवाडा द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपने जवाब में बताया है कि मौजा झुथरी की आ0न0 3532, 3533, 3534, 3535 कुल किता 4 रकबा 0.57 हैक्टर ,गत आराजी न. 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा मिसल नम्बर 1849/69 दिनांक 27/10/79 को तहसीलदार खैरवाडा द्वारा बिलानाम (सिवाचक) भूमि को नियमन श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम हुआ जिसका नामान्तरणकरण संख्या 161 खोला गया। जबकी खातेदार द्वारा उक्त आराजी को 1975 में ही प्रतिवादी स.1 को बेचान किया जिसका नामान्तरणकरण संख्या 400 बिना पंजीयन एवं नामान्तरणकरण संख्या 672 भी बिना पंजीयन दस्तावेज के हुए है। अतः वादीगण का आक्षेप बिना पंजीयन व मिलीभगत का साबित हो रहा है। बिना पंजीयन बेचान दस्तावेज को स्वीकार किया जाने से राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। पूर्व में प्रस्तुत दावा 125/2006 में गत(साविक) आ.न. 1159 रकबा 3 बीघा का है जबकी यह दावा गत (साविक) आ.न.2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा का है। अतः वाद संख्या 125/2006 के निर्णय से इस वाद का कोई सम्बन्ध नहीं है। दौराने कार्यवाही प्रतिवादी न.01 ने उपस्थित होकर दिनांक 24/03/2021 को प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. धारा 151 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी न.1 की तरफ से अधिवक्ता श्री बसन्त कुमार व्यास व दिलीप कुमार व्यास का वकालतनामा पेश किया गया। तत्पश्चात दिनांक 06/10/2023 को विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी न.1 से सम्पर्क नहीं होना मौखिक बताया। बार-बार आवाज लगाने पर भी प्रतिवादी न.01 न्यायालय समय पर उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही अमल में ली गई। तथा विपक्षी का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. धारा 151 जा.दी. का इसी स्टेज पर खारिज किया गया। वादीगण की तरफ से स्वयं वादीयां हीराबाई का गवाह के रूप में शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया। तथा दस्तावेज सबूत में साक्ष्य के रूप में नामान्तरकरण की प्रति प्रदर्श 1,जमाबन्दी सवन्त 2035 से 2038 प्रदर्श 2 ,मिलान योग प्रदर्श 3, पूर्व प्रकरण संख्या 125/2006 प्रदर्श 4 , फर्द प्रदर्श 5 , आदेशिका प्रदर्श 6, पत्रावली पाबन्द की प्रदर्श 7 व तहसीलदार का जवाब प्रदर्श 8। वादीगण के अधिवक्ता और कोई शहादत सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वादीगण की साक्ष्य बन्द की गई।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता की बहस अपने वाद-पत्र अनुसार रही मुख्य रूप से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा झुथरी की साविक आ. न. 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी स्वर्गीय दला पिता हकरा कुम्हार (प्रजापत) को नियमन से प्राप्त हुई थी। जिसपर वादीगण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है। जिसके नवीन सेटलमेंट की आ.न. 3532, 3533, 3534, 3535 कुल किता 4 रकबा 0.57 हेक्टर कायम होकर प्रतिवादी न.1 के खाते दर्ज है। पटवारी हल्का व प्रतिवादी न.1 की मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर खाता रद्दोबदल कर दिया है जो विधि विरुद्ध है। तहसीलदार खैरवाडा द्वारा दिनांक 23/01/2020 को जवाब दावा प्रतिवादी न. 2 के रूप में पेश किया है वह सही है। प्रस्तुत दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि भूमि का बेचान नामा है वह भी गलत व फर्जी है वास्तविक कोई दस्तावेज होता तो प्रतिवादी न.1 व उनके अधिवक्ता आवश्यक ही प्रस्तुत करते। लेकिन भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी द्वारा बेचान नहीं कि गई है। पटवारी व प्रतिवादी न. 1 की मिलीभगत से भूमि को हडपने की नियत से गलत बेचान नामा के आधार पर खाता खोला गया है जो अवैध होकर निरस्त योग्य है। पैरोकार प्रतिवादी न. 2 ने भी अपने जवाब में बताया गया है की प्रतिवादी न.1 एवं तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा अपंजिकृत दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 400 व दुसरा नामान्तरकरण संख्या 672 भूमि का हस्तान्तरण होना साबित होता है ऐसा दस्तावेज से सरकार को भी राजस्व हानि पहुचाई है। वादीगण के खाते दर्ज किया जाना तथा दावा डिकी किया जाना न्याय संगत होना बताया है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19/08/2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर आदेश दिया गया था कि अप्रार्थी सं.1 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे एवं नहीं किसी अन्य से करावें। वादगस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इसके बावजूद विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य चालू कर दिया जिसके वादीयां के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 15/03/2021 को प्रार्थना -पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी श्री नाथूलाल पिता मावजी पटेल निवासी झुथरी तहसील खैरवाडा को पुलिस इम्दाद द्वारा आप न्यायालय के आदेश की पालना करवा कर किये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाया जावे। तदनुसार न्यायालय द्वारा थानाधिकारी खैरवाडा को लिखा गया। विपक्षीगणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 02/03/2021 को पांबद किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 7 जा.दी. का प्रस्तुत करने के पश्चात मामले में कसी प्रकार कि चारा- जोही स्वयं प्रतिवादी अथवा उनक अधिवक्ता द्वारा नहीं कि हैं तथा विपक्षी अधिवक्ता दिलीप व्यास द्वारा दिनांक 06.10.2023 को विपक्षी से सम्पर्क नहीं होना मौखिक न्यायालय को बताया गया इसलिए विपक्षी संख्या 1 के विरुद्ध पूर्व से एकतरफा कार्यवाही चल रही थी ऐंसी स्थिति में विपक्षी नम्बर 1 का प्रार्थना -पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 7 जा.दी. व धारा 151 जा.दी का इसी स्टेज पर दिनांक 06.10.2023 को खारिज किया गया। उक्त मामले में भूमिधारी

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

प्रतिवादी स. 1 के नाम से नामान्तरकरण दर्ज करा कर फर्जी तरीके से खाते में अपना नाम दर्ज कर दिया जो की फर्जी दस्तावेज के आधार पर दर्ज किये जाने से उक्त इन्द्राज को दुरस्त कराया जाना न्यायहित में आवश्यक है। उक्त तथ्यों की जानकारी होने पर वादीगण ने अधिवक्ता स्व. गजानन्द शर्मा से सम्पर्क कर दावा करवाया जिसका नम्बर 125/2006 रा0वा0 आप न्यायालय में प्रस्तुत किया। वादी न.1 जो उम्रदराज है अधिवक्ता पर विश्वास कर पेशियों पर आती रही परन्तु इस दौरान अधिवक्ता का देहान्त हो जाने से वादीयां न. 1 को मामले में जानकारी नहीं मिल सकी तथा इसी दौरान वादीयां न. 1 ने जब भी न्यायालय में सम्पर्क किया तो भी वादीगण को सही जानकारी नहीं मिली। इसी दौरान राजस्व लोक अदालत में दिनांक 11/06/2016 को वादीयां सं. को कैम्प झुथरी में लोक अदालत में बुलवाया तथा राजस्व अधिकारीयो ने मामले में एक पक्षीय कार्यवाही करने का कहकर वादीयां के हस्ताक्षर करवा कर बताया की मामला फ़ैसल कर दिया है तथा अब आपको आने की जरूरत नहीं है। लेकिन दिनांक 30/1/2018 को उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादी न.1 द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जबरन जोर-शोर से जे.सी.बी. से उक्त भूमि के मध्य स्थित मगरी को समतल करवाने का कार्य करवाया जाकर वादीगण को बेदखल करने का प्रयास कर रहा था जिसकी जानकारी वादीयां स.1 जो कि उदयपुर में रहती है वादीयां को गाँव के लोगो द्वारा बताने पर वादीयां गाँव आई तथा गाँव के मातबीरो को एकत्र कर प्रतिवादी न.1 को कार्य करने से रोक दिया। परन्तु प्रतिवादी न. 1, वादीगण को आये दिन धमकाने लगा की उक्त भूमि मेरी है तथा खाते में भी मेरी होने से इसका उपयोग करूंगा तब वादीगण ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर पूर्व में प्रस्तुत मामले की जानकारी करने हेतु दिनांक 16/02/2018 को नकल प्रार्थना-पत्र लगाकर नकल प्राप्त की तो पता चला की उक्त वाद को दिनांक 11/06/2016 को राजस्व लोक अदालत में निर्णय कर दिया है तथा प्रकरण संख्या 125/2006 रा0वा0 में वादीगण के अधिवक्ता स्व.गजानन्द शर्मा ने उपरोक्त वाद वर्णित आराजीयात के बजाय वादीयां न.1 के पति स्व. दलाजी को आवंटित आराजी नम्बर 1159 रकबा 3 बीघा के सम्बन्ध में दावा कर दिया जो कि गलत नम्बर थे तथा गलत नम्बर होने के आधार पर कोई रिलीफ नहीं दिलाई जा सकती है यह कह कर वाद को खारिज कर दिया जिसकी वादीगण को कोई जानकारी नहीं थी न ही राजस्व अधिकारीयो ने वादीयां न. 1 को इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी दी। जानकारी के अभाव में वादीगण अपने पक्ष में निर्णित होना जान निश्चित हो गये तथा मौके पर भी वादीगण का कब्जा बदस्तुर चलता आ रहा है। वादीयां न.01 के पति ने कभी भी प्रतिवादी न. 1 को वाद वर्णित आराजीयात या उसका कोई हिस्सा विक्रय नहीं किया गया था। प्रतिवादी न. 1 ने पटवारी से मिली भगत कर अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण खोल दिया। जिसके सम्बन्ध में वादीगण ने उक्त अनरजिस्टर्ड दस्तावेज का अवलोकन कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी स. 1 द्वारा मना करते हुए उसके नाम से दर्ज होना का बताया एवं नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहा है जो कि अनुचित है। जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्यायहित में आवश्यक है साथ ही अवैध तरीके अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने का आदेश फरमावे। उक्त वाद वर्णित आराजीयात के स्वामित्व व अधिपत्य का होकर वादीगण ही उस पर काबिज होकर उपयोग -उपभोग करते आ रहे हैं। जिस पर प्रतिवादी न.01 अतिक्रमण कर अवैध रूप से जे0सी0बी0 लगाकर समतल करने अथवा किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने का कोई अधिकार नहीं है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णीय हानि होगी जिसका एवजाना असम्भव होगा वह अपने स्वामित्व की सम्पत्ति के उपयोग- उपभोग से वंचित हो जायेगा। ऐसे में वांछित निषेधाज्ञा जारी कराया जाना न्यायोचित है इस के अलावा वादीगण के पास कोई विकल्प नहीं है। वाद कारण सर्वप्रथम दिनांक 30.01.2018 को प्रतिवादी न. 1 द्वारा वादीगण के वर्णित वादग्रस्त आराजीयात पर जबरन अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर जे0सी0बी0 मशीन द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात के मध्य मगरी को समतल कराने का प्रयास किया जिस पर वादी गण द्वारा विरोध करने पर प्रतिवादी न.01 द्वारा गाली- गलौच कर मरने -मारने पर उतारू हो गया जिस से वाद पैदा हुआ तथा बाद में गाँव के मातबीरो द्वारा समझाईस करने पर प्रतिवादी न. 01 द्वारा उक्त अवैध कार्य रोक देने के बाद दिनांक 19/02/2018 को पूर्व में प्रस्तुत मामले(दावे) की नकल प्राप्त करने से उत्पन्न हुआ जो निरन्तर बना हुआ है। प्रतिवादी न. 1 द्वारा मिली- भगत कर फर्जी दस्तावेज बनाये जाकर उनके आधार पर नामान्तरकरण अपने नाम खुलवा लिया जो कि विधि सम्मत नहीं है। वादीगण उक्त वाद वर्णित आराजीयात के एक मात्र स्वामी हो, काबिज हो उपयोग - उपभोग करते आ रहे हैं परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 अपने धनबल व भूजबल के आधार पर बनाये गये फर्जी दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण खुलवा लिया जो की विधि विरुद्ध है। इसलिए मजबुरन यह दावा प्रतिवादी के विरुद्ध लाया गया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी न.1 का सम्मन तामिल होकर प्राप्त होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने से उसके विरुद्ध दिनांक 19/08/2019 को एक तरफा कार्यवाही अमल मे ली गई। प्रतिवादी न. 2

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
खेरवाड़ा, जि. उदयपुर (राज.)

तहसीलदार खैरवाड़ा द्वारा पूर्व दिनांक 13.01.2020 को प्रस्तुत जवाब दावा प्रदर्श 8 है जिसमें तहसीलदार खैरवाड़ा द्वारा भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी दला पिता हकरा कुम्हार को आवंटन से प्राप्त होना बताया है। तथा वादीगण ने उक्त भूमि पैतृक होना वाद पत्र में दर्शाया गया है ऐसी स्थिति में वाद का गुण एवं दोष के आधार पर सही निस्तारण हैतु न्यायालय द्वारा तहसीलदार खैरवाड़ा से आवश्यक राजस्व रेकॉर्ड तलब किया गया। नामान्तरण संख्या 400 की प्रमाणित नकल जिसमें आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा का विकार से नाथू पिता मावा पटेल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 672 के द्वारा आ0न0 2553 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा बिकाव से नाथु पिता मावा पटेल (जंगी) के नाम शेष 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। मौजा झुथरी की जमाबन्दी सवत 2031 से 2034 के खाता नम्बर 21 में श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम दर्ज है। खातेदार ने अपना पुरा हिस्सा 400 व 672 से श्री नाथु पिता मावा पटेल (जंगी) के नाम दर्ज हुई है जिसकी जमाबन्दी 2028 से 2031 के खाता नम्बर 18 की आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। जमाबन्दी सभ्यत 2024 से 2027 में नामान्तरण सं0 161 से श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम पर भिसल संख्या 1849/1969 दिनांक 27.10.1969 से नियमन होकर खातेदारी हक से दर्ज है। अपंजीकृत बेवान से नामान्तरण सं0 400 व 672 से अलग-अलग बेवान बताकर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी 2031 से 2034 के कॉलम संख्या 16 में वर्णित है। भूमि अनरजिस्टर्ड बेवान-पत्र से हुई हस्तान्तरण हुई है। भारतीय कानून में सम्पत्ति के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए पंजीकृत बिक्री विलेख आवश्यक है। म्युटेशन (नामान्तरण) केवल एक पंजीयन बिक्री विलेख के आधार पर ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरण अवैध होकर प्रभावहीन है। वादीगण स्व. दला पिता हकरा कुम्हार के हिन्दु उत्तराधीकारी नियम के तहत बलास वन के वारीसान है जिन्हें यह दावा लाने का पूर्ण अधिकार है। मामला एक पक्षीय हो चुका है। प्रस्तुत दावा साक्ष्य-सबूत से सिद्ध होता है ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिकी किया जाना उचित प्रतित होता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वाद वर्णित कृषि भूमि वादीगण के पूर्वाधिकारी श्री दला पिता हकरा कुम्हार (प्रजापत) को दिनांक 27/10/1969 को नियमन की गई थी तथा सन् 1975 में प्रतिवादी न. 1 को बेवान होना बताया है। इससे भी यह स्पष्ट जाहिर होता है कि पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी न.1 की मिलीभगत से भूमि अपंजीकृत बेवान नामों के आधार पर खाता रददी-बदल किया जाकर प्रतिवादी न. 1 के नाम खाता खोला गया है वह विधि विरुद्ध है। वाद वर्णित कृषि भूमि पर न्यायालय द्वारा दिनांक 19/08/2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर आदेश दिया गया था कि अप्रार्थी सं.1 मूल वाद के निस्तारण तक प्रार्थी के कब्जे काशत में किसी प्रकार का कब्जा नहीं करे एवं न ही किसी अन्य से करावे। वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। इसके बावजूद विपक्षी द्वारा निर्माण कार्य चालू कर दिया जिसके वादीयों के अधिकारता द्वारा दिनांक 15/03/2021 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विपक्षी श्री नाथूलाल पिता मावजी पटेल निवासी झुथरी तहसील खैरवाड़ा को पुलिस इन्चार्ज द्वारा आप न्यायालय के आदेश की पालना करवा कर किये जा रहे निर्माण कार्य को रूकवाया जावे। तदनुसार न्यायालय द्वारा थानाधिकारी खैरवाड़ा को लिखा गया। विपक्षीगणों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर दिनांक 02/03/2021 को पांबंद किया गया। न्यायालय द्वारा तहसीलदार खैरवाड़ा से आवश्यक राजस्व रेकॉर्ड तलब किया गया। नामान्तरण संख्या 400 की प्रमाणित नकल जिसमें आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा का विकार से नाथू पिता मावा पटेल के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है तत्पश्चात नामान्तरण संख्या 672 के द्वारा आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा बिकाव से नाथु पिता मावा पटेल (जंगी) के नाम शेष 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ है। मौजा झुथरी की जमाबन्दी सवत 2031 से 2034 के खाता नम्बर 21 में श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम दर्ज है। खातेदार ने अपना 1/2 हिस्सा व नामान्तरकरण संख्या 400 व नामान्तरकरण संख्या 672 से 1/2 हिस्सा श्री नाथु पिता मावा पटेल (जंगी) के नाम दर्ज हुई है जिसकी जमाबन्दी 2028 से 2031 के खाता नम्बर 18 की आ0न0 2853 रकबा 3 बीघा 1 विस्वा श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम खातेदारी हक से दर्ज है। जमाबन्दी सभ्यत 2024 से 2027 में नामान्तरण सं0 161 से श्री दला पिता हकरा कुम्हार के नाम पर भिसल संख्या 1849/1969 दिनांक 27.10.1969 से नियमन होकर खातेदारी हक से दर्ज है। अवैधानिक बेवान से नामान्तरण सं0 400 व 672 से अलग-अलग बेवान बताकर तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा जमाबन्दी 2031 से 2034 के कॉलम संख्या 16 में वर्णित है। भूमि अनरजिस्टर्ड बेवान-पत्र से हस्तान्तरित हुई है। भारतीय कानून में सम्पत्ति के स्वामित्व को स्थापित करने के लिए पंजीकृत बिक्री विलेख आवश्यक है। म्युटेशन (नामान्तरण) केवल एक पंजीयन बिक्री विलेख के आधार पर ही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विवादित नामान्तरण अवैध होकर प्रभावहीन है। वादीगण स्व. दला पिता हकरा कुम्हार के हिन्दु उत्तराधीकारी अधिनियम 1956 के तहत बलास वन के वारीसान है जिन्हें यह दावा लाने का पूर्ण

उत्तराधीकारी अधिनियम 1956 के तहत बलास वन के वारीसान है जिन्हें यह दावा लाने का पूर्ण अधिकार है।

उत्तराधीकारी अधिनियम 1956 के तहत बलास वन के वारीसान है जिन्हें यह दावा लाने का पूर्ण अधिकार है।

अधिकार है। मामला एक पक्षीय होने से तनकी वार निस्तारण नहीं लिखा गया। प्रतिवादी द्वारा अपना जवाब नहीं किया गया है तथा न ही अपने पक्ष में लिखे गये अनरजिस्टर्ड दस्तावेजों को भी पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी न.01 द्वारा उक्त मामले में किसी प्रकार की चाराजोही नहीं की है न ही स्वयं उपस्थित हुआ है। व नामान्तरण संख्या 400 व 672 में जिन दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है उक्त दस्तावेज नामान्तरकरणों के साथ चरपा नहीं है न ही प्रतिवादी संख्यां 01 द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। वादीगण द्वारा अपने मौखिक बयान व दस्तावेजों से भी वादीगण का वाद साबित है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:-

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाता है कि मौजा- झुथरी की आ. नं. 3532/0.04, 3533/0.04, 3534/0.03, 3535/0.46 कुल किता 4 रकबा 0.57 हेक्टर कृषि भूमि के एक मात्र खातेदार वादीगण को घोषित किये जाते हैं। अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्यां 400 व 672 को ( NULL AND VOID) प्रभावहीन घोषित किये जाकर निरस्त किये जाते हैं। तथा प्रतिवादी न0 01 के विरुद्ध इस आशय का रथाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जे-काश्त में किसी प्रकार कि दखलन्दाजी नहीं करे। प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा दौराने वाद कोई अवैध निर्माण अथवा कब्जा कर दिया जाता उसे स्वयं प्रतिवादी नम्बर 01 के खर्च से तुडवाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम की जावे। डिक्री पर्चा अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खैरवाड़ा एवं थानाधिकारी खैरवाड़ा को भिजवाया जावे। तहसीलदार खैरवाड़ा व थानाधिकारी खैरवाड़ा मुताबिक डिक्री पालना कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करावें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय आज दिनांक 09 / 10 / 2025 को सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
पञ्जाब कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
खैरवाड़ा, पंजाब, कि. डेक्कन (दि.नु0)

डिगरी व मुकदमे हवाई

(आ 2 रुल 6-7 जाब्ला दीवानी)

अज अदालत - सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी-खैरवाडा, जिला-उदयपुर (राज.)  
निर्णय द्वारा पीठसीन अधिकारी - श्री जयसिंह- 11 (RAS)

श्रीमति हीरा बाई बेवा स्व. दलाजी प्रजापत, जाति- प्रजापत, वगैरह निवासी - शुथरी, तहसील- खैरवाडा  
जिला- उदयपुर (राज.) क. स. 1 से 05 तक.

श्री नाथु पिता मावा जी पटेल, जाति-पटेल, निवासी- निवासी - शुथरी, तहसील- खैरवाडा जिला- उदयपुर  
दावा- वाद बाबत घोषणा, निषेधाज्ञा एवं इन्जाज दुरुस्ती।  
(राज.) क.स.01से 02 तक।  
मुकदमा नम्बर -07/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन्किसाल कतई खबर- हमारे  
मिनजानिब मुददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

ग्राम - मौजा- शुथरी की आ. न. 3532/0.04, 3533/0.04, 3534/0.03, 3535/0.46 कुल कितता 4  
रकबा 0.57 हेक्टर कृषि भूमि के एक मात्र खतेदार वादीगण को घोषित किये जाते है। अपंजीकृत  
दस्तावेज के आधार पर खते गये नामान्तरकरण सख्यां 400 व 672 को ( NULL AND VOID)  
प्रभावहीन घोषित किये जाकर निरस्त किये जाते है। तथा प्रतिवादी न0 01 के विरुद्ध इस आशय का  
रखाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वादीगण के कब्जे-काशत में किसी प्रकार कि दखलन्दानी नही  
करे। प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा दौराने वाद कोई अवैध निर्माण अथवा कब्जा कर दिया होतो उसे  
स्वयं प्रतिवादी नम्बर 01 के खर्च से तुडवाया जाकर पूर्ववत स्थिति कायम की जावे। डिक्री पर्चा  
अलग से जारी होकर पालना हेतु तहसीलदार खैरवाडा एवं थानाधिकारी खैरवाडा को भिजवाया जावे।  
तहसीलदार खैरवाडा व थानाधिकारी खैरवाडा मुताबिक डिक्री पालना कर पालना रिपोर्ट इस  
न्यायालय को पेश करावें।  
मुखलिया - -- वाबत -- खर्चा इस मुकदमें के मय सुद व शहर-

फसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसुलीगवी तक - का अदा  
करें।

वसुला मेरे दस्तखत व मूहर अदालत से आज तारीख 09 माह 10 सन् 2025 को  
जारी की गई।

दस्तखत -  
ओहदा - सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
खैरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)

मुदई रुपया पैसा मुदायता रुपया पैसा	
स्टाम्प अरजी दावा = 6.00/-	स्टाम्प अरजी वकालत नामा = -/-
स्टाम्प वकालतनामा = 1.00/-	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबुत	स्टाम्प वजह सबुत
महनताना वकील (फा.)	महनताना वकील (फा.)
बाबत इजराय हुक्मनामा	बाबत इजराय हुक्मनामा
खर्चा गवाहान	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
मुतफरिक = 2.00/-	मुतफरिक

मीजान :- 9:00/- मीजान :- = -/-